

प्रेषक, बी० लाल,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तरांचल शासन

सेवा में,
महाधिवक्ता,
उत्तरांचल,
मा० उच्च न्यायालय परिसर,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग : देहरादून : दिनांक- 23 अक्टूबर, 2003
विषय : मुख्य स्थायी अधिवक्ता/स्थायी अधिवक्ताओं द्वारा शासन से निर्गत आदेशों के अनुसार पुनर्विचार प्रार्थना पत्र दायर न किया जाना व न ही मा० न्यायालय में चल रहे केसेज के सम्बन्ध में गम्भीरता से अनुश्रवण किये जाने विषयक ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में आवकारी विभाग के केसेज में श्री सुभाष उपाध्याय, ब्रीफ होल्डर द्वारा ^{काबल रखे} विभाग को गुमराह किये जाने व दिनांक-10-10-2003 के मा० उच्च न्यायालय के आदेशों की सूचना दिनांक-16-10-2003 से पूर्व शासन के प्रशासकीय विभाग को न दिये जाने पर सरकारी अधिवक्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य स्थायी अधिवक्ता/स्थायी अधिवक्ताओं द्वारा शासन से निर्गत आदेशों के अनुसार पुनर्विचार प्रार्थना पत्र दायर न किये जाने व न ही मा० उच्च न्यायालय में चल रहे केसेज के सम्बन्ध में गम्भीरता से अनुश्रवण किये जाने के विन्दु पर अपनी जाँच आख्या तत्काल शासन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(बी० लाल)
सचिव ।